राष्ट्रीय सागर | झारखण्ड मंगलवार | रांची, 11 नवंबर 2014

संस्कृति की जड़ों से जोड़ती नई शिक्षा-व्यवस्था

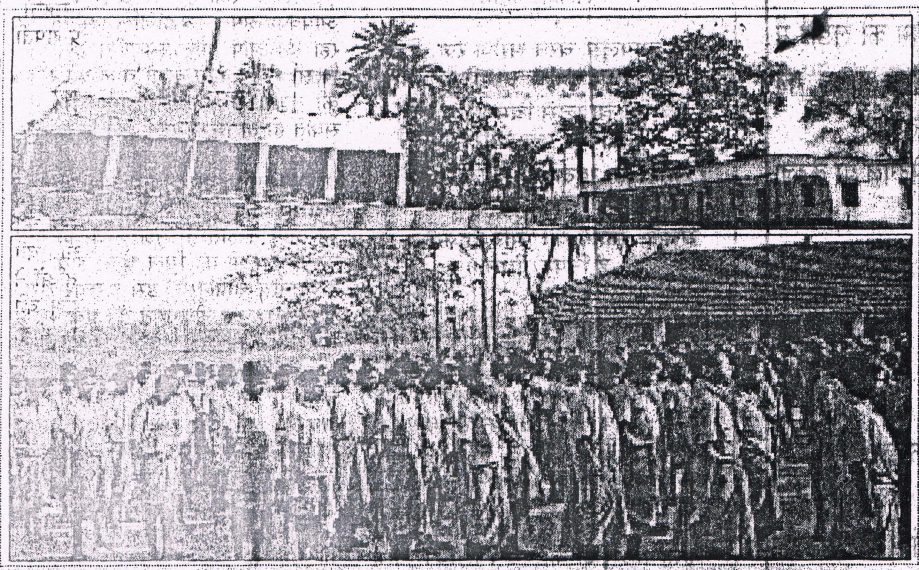

जसिन्ता केरकेट्टा

भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। देशभर में मातृभाषा में शिक्षा की मांग हो रही है लेकिन इस दिशा में अबतक कोई पहल सरकार ने नहीं किया है। वहीं झारखंड से सटे पड़ोसी राज्य ओड़िशा में मातृभाषा में शिक्षा की पहल हो चुकी है। इसका अच्छा परिणाम भी सामने आ रहा है। जहां झारखंड सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है वहीं साहेबगंज जिले के संताल-पहाड़िया आदिवासियों ने अपनी ओर से इसकी प कर दी है। साहेबगंज जिले में संथाल व पहाड़ियाओं का विश्वास सरकारी स्कूलों से उठ रहा है। इसका प्रमाण यह है कि कई गांवों के लोग सरकारी स्कूल से बच्चों को निकाल रहे हैं। संथाल व पहाड़िया अभिभावक अपने प्रयास से अलग स्कूल चला रहे हैं, जहां वे सरकारी स्कूल से हटाकर अपने बच्चों को डाल रहे हैं। यहां प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जा रही है। साथ ही अपनी संस्कृति से भी बच्चों को जोड़े रखने का प्रयास किया जा रहा है। अभिभावकों का मानना है कि सरकारी स्कूल बच्चों को अपनी संस्कृति से काटता है। सरकारी स्कूलों में परीक्षा लेने का प्रावधान भी नहीं है। हर बच्चा यूं ही उंची कक्षाओं में प्रवेश पा जाता है। उसके ज्ञान का आंकलन नहीं हो पाता। ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की समझ विकसित नहीं होती। ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जो बच्चों को सिर्फ डिग्री दिलाए लेकिन वे अंततः पढे-लिखे गंवार ही रहे। सरकारी स्कूल दो तरफ से आदिवासी समाज को हानि पहुंचा रहा। एक तो नई पीढ़ी को सही शिक्षा, समझ, ज्ञान नहीं दे पा रहा और दूसरी ओर पूरी तरह से अपनी संस्कृति से बच्चे कट रहे। शिक्षा के नाम पर यह एक षडयंत्र है। ऐसी शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को बेकार बनाएगी। इससे बचने के लिए वे अपने तरीके से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे।

पारंपरिक परिधान में स्कूल जाते संथाल बच्चे : जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कदमा स्थित सबैंया गांव का फा-अंथोनी मुर्मू स्कूल सोना संताल समाज समिति के द्वारा संचालित है। 1991 में यह स्कूल खोला गया था। सामाजिक कार्यकर्ता और बाद में पूर्व सांसद अंथोनी मुर्मू की हत्या बांझी हत्याकांड में हो गई थी। फादर अंथोनी से करीबी रिश्ता होने के कारण जेसुईट पुरोहित फादर टॉम 1985 में इस क्षेत्र में आए और उनके सपनों को जिंदा रखने का काम किया। फा-अंथोनी मुर्मू के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सोना संताल समिति का निर्माण किया गया। इसी समिति द्वारा संचालित स्कूल में ज्यादतर बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़कर प्रवेश किया है। यहां बच्चों में अनुशासन है। निचली कक्षाओं में संताली भाषा से ही पढ़ाई होती है। प्रकृति के बीच उन्हें शिक्षा दी जाती है। बच्चे अच्छी हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा की समझ भी सरकारी स्कूल के बच्चों की अपेक्षा अधिक है। स्कूल की खासियत यह है कि सप्ताह के एक दिन लड़के-लड़कियां पारंपरिक वस्त्र लूंगी-पंची में स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के अधिकांश शिक्षक इसी स्कूल से पढ़कर निकले पूर्ववर्ती विद्यार्थी हैं। फादर टॉम कहते कि प्रारंभ में क्षेत्र में साक्षरता की कमी थी। जिसके कारण लोग महाजनों के हाथों ठगे जाते थे। जिसके लिए लोगों में साक्षरता बढ़ाना जरूरी समझ स्कूल की षुरूआत की गई। ताकि भावी पीढ़ी महाजनों की षिकार न बने। आज काफी कुछ बदल गया है। अभिभावकों में शिक्षा को लेकर जागरूकता आयी है। अभिभावक स्वयं ही बैठक करते हैं और समस्याओं पर चर्चा करते हैं। गांव-समाज स्वयं बच्चों की बेहतरी के निर्णय लेते हैं।

पहाड़िया-संथालियों का अकिल अखड़ा स्कूल : दूसरी ओर संताल व पहाड़िया अभिभावकों ने संजू मरांडी के प्रयास से पहाड़पुर में अकिल अखड़ा प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया है। पहाड़पुर गांव के मरांग मुर्मू ने अपने आवास को बच्चों के लिए छात्रावास बना दिया है। तीन-चार कमरे में बच्चों की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में करीब 70 बच्चे हैं। संथाल-पहाड़िया समाज के शिक्षित लड़के-लड़कियां इस स्कूल में बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए उन्हें संथाली गीत सिखाए जाते हैं। वे खेती करने की प्रक्रिया सीखते हैं। संथाली व पहाड़िया बच्चे अपनी भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर भी पकड़ बना रहे हैं। इस स्कूल की संचालिका व प्रचार्या संजू मरांडी हैं।

पहाड़ व तराई इलाके के करीब 25 गांवों से बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं।

संजू मरांडी का कहना है कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना जरूरी है। कई बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर यहां पढ़ाई कर रहे और उनकी समझ विकसित हो रही। अभिभावकों व लोगों के सहयोग से यह स्कूल चल रहा है। हाल ही में खाद्य आपूर्ति मंत्री लोबिन हेम्ब्रोम ने बच्चों के बीच ड्रेस व स्कूल बैग का वितरण किया है। अभिभावक फीस के लिए चावल और कुछ पैसे जमा करते हैं। मातृभाषा में षिक्षा जरूरी है जिसकी जरूरत और अहमियत सरकार नहीं समझ रही।

सीएसडीएस द्वारा प्रदत्त इनक्लूसिव मीडिया यूएनडीपी फेलोशिप के तहत रिपोर्टिंग